



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-02072024-255095  
CG-WB-E-02072024-255095

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 475]  
No. 475]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 2, 2024/आषाढ 11, 1946  
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 2, 2024/ASHADHA 11, 1946

यूको बैंक

(प्रधान कार्यालय:कोलकाता)

अधिसूचना

कोलकाता, 1 जुलाई, 2024

फा.सं.-एचओपीएसडी/पेंशन/2024-25/50-(ई).—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5वां), की धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करने और केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के पश्चात एतद द्वारा यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

- (1) इन विनियमों को यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।  
(2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 (इसके पश्चात उक्त विनियम के रूप में संदर्भित) में, विनियम 2 के, खंड(ध), उप-खंड (घ) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, यथा:-

“परंतु 01 नवंबर, 2012 से लागू किए गए विशेष भत्ते को शामिल नहीं किया जाएगा:

परंतु यदि कोई कर्मचारी जो 01 नवंबर, 2017 को बैंक की सेवा में था और जिसकी स्टेगनेशन वेतनवृद्धि उसके वेतन के अधिकतम स्तर तक पहुंचने की तारीख से संशोधित आवधिकता के अनुसार फिर से समायोजित की गई है, वह पेंशन के प्रयोजनों के लिए 01

नवंबर, 2017 से इस तरह के संशोधित स्टेगनेशन वेतनवृद्धि/(यों) के लिए नोशनल रूप से पात्र होगा, लेकिन इस तरह के पुनः समायोजन के कारण मौद्रिक लाभ केवल 01 नवंबर, 2020 से या पात्रता की वास्तविक तिथि, जो भी बाद में हो, से देय होगा।”

3. उक्त विनियमों के विनियम-22 में उप-विनियम(01)में निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा:

“परंतु कोई कर्मचारी, जो पूर्णकालिक कार्य पर स्थायी आधार पर या स्केल वेतन पर स्थायी आधार पर अंशकालिक कार्य परश्रमिक के रूप में बैंक की सेवा में नियोजित है, उसे हटाए जाने की स्थिति में, उसकी संपूर्ण पिछली सेवा जव्त नहीं होगी और वह पेंशन संबंधी लाभों के लिए अर्ह होगा।”

4. उक्त विनियमों के विनियम-36 में खंड(च) के पश्चात, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, यथा:-

(छ) अंशकालिक कर्मचारी को छोड़कर किसी कर्मचारी के संबंध में तीन हजार नौ सौ पचासी रुपये प्रतिमाह, जहां कर्मचारी 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो, 1/3 वेतनमान का वेतन प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में एक हजार तीन सौ पैंतीस प्रतिमाह, 1/2 वेतनमान का वेतन प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में दो हजार रुपये प्रतिमाह, और 3/4 वेतनमान का वेतन प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में तीन हजार रुपये प्रतिमाह, जहां अंशकालिक कर्मचारी 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो।

5. उक्त विनियमों के विनियम-40 में,-

(क) उप-विनियम (1) में,-

(i) खंड (बी) में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“परंतु यदि पात्र पुत्र या पुत्री सरकारी या निजी क्षेत्र या स्व-रोजगार से प्रतिमाह बारह हजार रुपये से अधिक राशि अर्जित करने लगे तो पुत्र या पुत्री (विधवा/तलाक़शुदा सहित) को देय पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी या स्वीकार्य नहीं होगी,”:

(ii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ग) माता-पिता के मामले में, पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी या स्वीकार्य नहीं होगी यदि माता-पिता में से किसी एक की आय या माता-पिता दोनों की कुल आय सरकारी या निजी क्षेत्र या स्व-रोजगार से प्रति माह बारह हजार रुपये से अधिक हो,”;

(ख) उप-विनियम (4)में, -

(i) खंड (क) में, उप-खंड(vi) के पश्चात, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, यथा:-

“(vii) छब्बीस हजार पांच सौ साठ रुपये प्रतिमाह मात्र उन कर्मचारियों को, अधिकारियों और कामगारों दोनों के संबंध में, जो 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या उनकी मृत्यु हो गई हो।”

परंतु 01 अप्रैल 2021 से और उसके बाद, उप-खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं रह जाएगा और उपर्युक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि विनियम-39 के उप-विनियम (3) के खंड (क) के उप-खंड (i) और खंड (ख) के उप-खंड (i) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।”;

(ii) खंड (ख)में, उप-खंड (vi) के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, यथा:-

“(vii) छब्बीस हजार पांच सौ साठ रुपये प्रतिमाह मात्र उन कर्मचारियों को, अधिकारियों और कामगारों दोनों के संबंध में, जो 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या उनकी मृत्यु हो गई हो।”

परंतु 01 अप्रैल 2021 से और उसके बाद, उप-खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं रह जाएगा और उपर्युक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि विनियम 39 के उप-खंड (1) या उक्त विनियम के उप-विनियम (3) के खंड (क) के उप-खंड (i) और खंड (ख) के उप-खंड (i) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी, जैसा भी मामला हो।”;

(iii) खंड (ग) में, उप-खंड (vi) के पश्चात, निम्नलिखित उप-खंड जोड़े जाएंगे, यथा:-

“(vii) तेरह हजार दो सौ अस्सी रुपये प्रतिमाह मात्र उन कर्मचारियों को, अधिकारियों और कामगारों दोनों के संबंध में, जो 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या उनकी मृत्यु हो गई हो।”

परंतु 01 अप्रैल 2021 से और उसके बाद, उप-खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं होगा और उपर्युक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि विनियम 39 के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।”;

6. उक्त विनियमों के परिशिष्ट-II में, खंड(4) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(4) 1 मई, 2005 को या उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, 1960=100 शृंखला में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2288 बिन्दुओं से अधिक प्रत्येक 4 बिन्दुओं पर प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक कमी के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो। उक्त प्रत्येक 4 बिंदुओं के लिए महंगाई राहत में इस तरह की वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.18 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

परंतु 01 मई 2005 को या और उसके बाद से, उन कर्मचारियों के संबंध में जो 01 नवंबर 2002 को या उसके बाद लेकिन 30 अप्रैल 2005 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, महंगाई राहत इस खंड के संदर्भ में देय होगी:

परंतु आगे कि 1 नवंबर, 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, 1960=100 शृंखला में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2836 बिन्दुओं से अधिक प्रत्येक 4 बिन्दुओं पर प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक कमी के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो। उक्त प्रत्येक 4 बिंदुओं के लिए महंगाई राहत में इस तरह की वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.15 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

परंतु यह भी कि 1 नवंबर, 2012 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, 1960=100 शृंखला में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 4440 बिन्दुओं से अधिक प्रत्येक 4 बिन्दुओं पर प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक कमी के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो। उक्त प्रत्येक 4 बिंदुओं के लिए महंगाई राहत में इस तरह की वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.10 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

परंतु यह भी कि 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, 1960=100 शृंखला में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 6352 बिन्दुओं से अधिक प्रत्येक 4 बिन्दुओं पर प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक कमी के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो। उक्त प्रत्येक 4 बिंदुओं के लिए महंगाई राहत में इस तरह की वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.07 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

7. उक्त विनियमों के परिशिष्ट-III में, खंड(च) के पश्चात, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, यथा:-

“(छ) 01 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा अन्य कार्मिकों (अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों) के संबंध में :

प्रतिमाह वेतनमान	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)
रु.15880/-तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगा तथा भत्ते का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जिसे भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी।

	परंतु मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की कुल राशि न्यूनतम 3,985 रुपये प्रतिमाह होगी।
रु.15881/-से रु.31760/-तक	वेतन का 20 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगा तथा भत्ते का अतिरिक्त 20 प्रतिशत, जिसे भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी। परंतु मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की कुल राशि न्यूनतम 4,900 रुपये प्रतिमाह होगी।
रु.31760/- से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगा तथा भत्ते का अतिरिक्त 15 प्रतिशत, जिसे भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी। परंतु मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की कुल राशि न्यूनतम 6,365 रुपये प्रतिमाह एवं अधिकतम 13,280 रुपये प्रति माह होगी।

(ज) 1 अप्रैल, 2021 को और उसके बाद से खंड (क) से (ख) प्रभावी नहीं रह जाएंगे तथा उक्त खंडों में उल्लिखित सभी कर्मचारियों (अधिकारी और कामगार दोनों) के संबंध में वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन तथा इसके अतिरिक्त भत्ते का 30 प्रतिशत, जिसे भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी।

#### स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन

जिन विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है, वे इस संबंध में संबंधित बैंकों के द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर उनकी ओर से भारतीय बैंक संघ तथा बैंकों के शीर्ष स्तरीय कामगार यूनियनों और अधिकारियों के एसोसिएशनों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते और संयुक्त नोट के सहमत निबंधन एवं शर्तों के अनुसार है। इसलिए, इस तरह के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अंबिकानन्द झा, महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./244/2024-25]

**टिप्पणी:** मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या पीईआर/पीईएन/265/95, दिनांक 29 सितंबर, 1995 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से अधिसूचना संख्या एचओपीएसडी/पेंशन/2023-24/67, दिनांक 18 अगस्त, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

### UCO BANK

(Head Office: Kolkata)

#### NOTIFICATION

Kolkata, the 1st July, 2024

**F. No. HOPSD/Pension/2024-25/50--(E)--**In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the UCO Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the UCO Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:-

- (1) These regulations may be called the UCO Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the UCO Bank (Employees') Pension Regulations, 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, in clause (s), in sub-clause (d), the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided further that special allowance introduced with effect from the 1<sup>st</sup> day of November, 2012 shall be excluded:

Provided also that an employee who was in the services of the Bank as on the 1<sup>st</sup> November, 2017 and whose stagnation increments have been re-adjusted as per revised periodicity from the date of reaching their maximum scale of pay, shall be notionally eligible for such revised stagnation increments with effect from the 1<sup>st</sup> November, 2017 for the purposes of Pension but the monetary benefit on account of such re-adjustment shall be payable only with effect from the 1<sup>st</sup> November, 2020 or the actual date of entitlement, whichever is later”.

3. In Regulation 22 of the said regulations, in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the removal of an employee, who is employed in the service of the Bank as a workman on full time work on permanent basis or on part-time work on permanent basis on scale wages, shall not entail for forfeiture of his entire past service and shall qualify for pensionary benefits.”.

4. In Regulation 36 of the said regulations, after Clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

“(g) rupees three thousand nine hundred and eighty-five per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after the 1st day of November, 2017, rupees one thousand three hundred and thirty-five per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees two thousand per month in respect of part-time employee drawing 1/2 scale wages, and rupees three thousand per month in respect of a part-time employee drawing 3/4 scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of November, 2017”.

5. In regulation 40 of the said regulations,-  
(a) in sub-regulation (1),-

(i) in clause (b), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that the family pension payable to son or daughter (including widowed or divorced) shall be discontinued or not be admissible when the eligible son or daughter starts earning a sum in excess of rupees twelve thousand per month from employment in Government or private sector or self-employment etc.”

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

“(c) in the case of parents, the family pension shall be discontinued or not be admissible if the income of one of the parents or the aggregate income of both the parents from employment in Government or Private sector or self – employment, exceeds rupees twelve thousand per month;”;

(b) in sub-regulation (4),-

(i) in clause (a), after Sub-clause (vi), the following shall be inserted, namely:-

“(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November 2017:

Provided that on and from the 1<sup>st</sup> day of April, 2021, sub-clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of both pensions for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-clause (i) of clause(a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 39.”;

(ii) in clause (b), after sub-clause(vi), the following shall be inserted, namely:-

“(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1<sup>st</sup> day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of both the pension for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-clause (1) of regulation 39 or sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of the said regulation, as the case may be.”;

(iii) in clause (c), after the sub-clause (vi), following sub-clauses shall be inserted, namely:-

“(vii) thirteen thousand two hundred and eighty only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1<sup>st</sup> day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of the two pensions for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-regulation (1) of regulation 39.”.

6) In Appendix-II to the said Regulations, for clause (4), the following shall be substituted, namely:-

“(4) In respect of employees who retire on or after the 1<sup>st</sup> May, 2005, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.18 per cent. of basic pension:

Provided that on and from the 1<sup>st</sup> day of May, 2005, in respect of employees who retired on or after the 1<sup>st</sup> day of November, 2002 but on or before the 30<sup>th</sup> day of April, 2005, dearness relief shall be payable in terms of this clause:

Provided further that in respect of employees who retired on or after the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.15 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1<sup>st</sup> day of November, 2012, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.10 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1<sup>st</sup> day of November, 2017, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.07 per cent of basic pension.”.

7) In Appendix-III to the said regulations, after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(g) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1<sup>st</sup> day of November, 2017:

<b>Scale of pay per month</b>	<b>Amount of monthly Family Pension</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
Upto Rs.15,880	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowance which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.3,985 per month.
Rs.15,881 to Rs.31,760	20 per cent. of the pay shall be basic family pension and additional 20 per cent. of allowance which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.4,900 per month.
Above Rs.31,760	15 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 15 per cent. of allowances which are counted for making contributions to provident fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension. Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.6365 per month and maximum of Rs.13,280 per month.

(h) On and from the 1st day of April, 2021 clauses (a) to (g) shall cease to have effect and in respect of all employees (both officers and workmen) mentioned in the said clauses, 30 per cent of the Pay shall be the

basic family pension plus 30 per cent of allowance which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension.”.

### EXPLANATORY MEMORANDUM

The regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlements and Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level workmen unions and officers' associations of the banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

AMBIKANAND JHA, General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./244/2024-25]

**Note:** The principal regulations were published in Gazette of India, Part III, Section 4 vide notification number PER/PEN/265/95, dated the 29<sup>th</sup> September, 1995 and lastly amended vide notification number HOPSD/ Pension/ 2023-24/67, dated the 18<sup>th</sup> August, 2023.